P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika
E: ISSN NO.: 2349-980X Vol-III* Issue-V* January-2016

छ.ग. में मानव संसाधन का विश्लेषणात्मक अध्ययन (आउटसोर्सिंग के संबंध में)

काजल परगनिहा
अतिथि सहायक प्राध्यापक,
वाणिज्य विभाग,
शा.नवीन महाविद्यालय,
खुर्सीपार

सारांश

राज्य में प्राकृतिक संसाधन के साथ–साथ मानव संसाधन भी बहुत महत्वपूर्ण होते है क्योंकि राज्य में अगर प्राकृतिक संसाधन लबालब भरें हों तब भी वह मानव संसाधन के बिना छिपी संपत्ति ही होगी क्योंकि मानव संसाधन ही उसका दोहन करके उसे उपयोगी रूप प्रदान करता है।

छ.ग. भी मानव संसाधन और वो भी शिक्षित मानव संसाधनों से भरा पड़ा है बावजूद इसके यहॉ शिक्षकों, डॉक्टरो और नर्सों की नियुक्ति बाहृय राज्यों से करने की कवायद जारी है। यह प्रथम दृष्टया राजनैतिक दाँव पेंच से ओत–प्रोत निर्णय जान पड़ता है और इस निर्णय से क्षेत्रीय बेरोजगारों का मनोबल टूटा है। क्षेत्रीय योग्यता का हनन हुआ है। इस शोध विषय को चुनने का मुख्य कारण यही था कि आंकड़ों द्वारा इस बात को सिद्ध करना कि छ.ग. शिक्षित जनों से भरा पड़ा है। इस तरह के निर्णय लिये ही नहीं जाने चाहिए जिसके दूरगामी दुष्परिणाम राज्य के बेरोजगारों को सहन करना पड़े।

राज्य के विकास के लिए गये निर्णयों में राज्य का हित सर्वोपरि होना चाहिए पर राज्य की जनता को साथ लेकर उन्हें छोड़कर नहीं।

मुख्य शब्द : मानव संसाधन, विश्लेषणात्मक अध्ययन, आउटसोर्सिंग।

प्रस्तावना

मानव संसाधन राज्य का वह हिस्सा है जो प्राकृतिक संसाधन क दोहन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मानव संसाधन की उत्तम प्रकृति किसी राज्य या राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होती है। मानव संसाधन का प्रबंधन अगर सही तरीके से हो तो राजनैतिक, सामाजिक, शिक्षण संस्थान या अन्य जगह जहाँ पर मानव संसाधन अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। आसानी से सफलता हासिल कर सकते है।

उत्पादन के पाँच साधन भूमि पूंजी श्रम साहस और संगठन में केवल श्रम ही एक सक्रिय साधन है, जो पूंजी को जमा करते है, प्राकृतिक साधनों को दोहन एवं सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक संगठनों का निमार्ण करते है, इसका मूल अर्थ राजनैतिक अर्थ व्यवहार और अर्थशास्त्र से लिया गया है।

मानव संसाधन दो प्रकार के होते हैः

1. प्राकृतिक संसाधन
2. मानव संसाधन

छ.ग. मे मानव संसाधन के स्वरूप को अगर हम देखें तो यहा वर्तमान जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार 2,5540196 (2.55 करोड़) है जिसमें पुरूष 12827915 (1.28) और महिलायें 12712281 (1.27 करोड़) हैं। यह भारत में 16वें न. पर है। यहा का जनसंख्या घनत्व 189 प्रतिवर्ग किमी है। लिंग अनुपात 991 है, जो भारत के औसत लिंग अनुपात से कहीं बेहतर है।

छ.ग. मानव संसाधन में समृद्ध राज्य है। छ.ग. 2001 की जनगणना देखें तो शिक्षा दर 64.66% था जिसमें 75.70 पुरूष और 55.73 महिलाएं थी पर अभी 2011 के जनगणना के अनुसार 70.28% पुरूष 59.58% महिला साक्षर है। संख्या में कुल शिक्षित 15379922 है जिसके 8,807893 पुरूष एवं 6572029 महिलायें है। वर्तमान मे शिक्षा को दर 71.04% यह भारत में 27वें स्थान पर है। जो बहुत बुरी स्थिति को बताता है। ऐसी स्थिति आदिवासी क्षेत्रों के कम शिक्षित होने की वजह से है सरकार उन्हें शिक्षित करने का प्रयास कर रही है। आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न प्राथमिक, माध्यमिक, हायर सेकेन्डरी स्कूल एवं महाविद्यालय खोले गये है लेकिन लगातार वहां शिक्षकों की कमी बनी हुई है ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षितो की सर्वाधिक संख्या शहरों से जैसे दुर्ग–भिलाई, रायपुर, बिलासपुर से है और ऐसे छात्र सुख सुविधाओं को छोड़कर इन बीहड़ों मे जाकर सेवा नहीं देना चाहते है जिसकी वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है इन बीहड़ों से लगे हुये अन्य राज्य के छात्रों को आकर्षक वेतन देकर उन्हें यहां आने

के लिए आकर्षित किया जा रहा है। जब यहा इतनी बड़ी जनसंख्या शिक्षित है तो आदिवासी क्षेत्रों के स्कूल में शिक्षण के लिए बाह्य शिक्षको को बुलाने का औचित्य समझ से परे है।

छ.ग. में 2011 के अनुसार जिलेवार शिक्षा का प्रतिषत निम्नलिखित है–

2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर

क्र. सं.	18 जिले		क्र. सं.	27 जिले	
1.	दुर्ग	79.06	1.	दुर्ग	82.56
			2.	बेमेतरा	69.87
			3.	बलोद	80.28
2.	धमतरी		4.	धमतरी	78.36
3.	राजनांदगाव	75.96	5.	राजनांदगाव	75.96
4.	रायपुर	75.69	6.	रायपुर	80.52
			7.	बलौदाबाजार	70.63
			8.	गरियाबंद	68.26
5.	रायगढ़	73.6	9.	रायगढ़	73.26
6.	जाजंगीर–चाम्पा	73.07	10.	जाजंगीर–चाम्पा	73.07
7.	कोरबा	72.37	11.	कोरबा	72.37
8.	महासमुंद	71.02	12.	महासमुंद	71.02
9.	बिलासपुर	70.78	13	बिलासपुर	70.78
			14.	मुंगेली	64.75
10.	कोरिया	70.64	15.	कोरिया	70.64
11.	कांकेर	70.29	16.	कांकेर	70.29
12.	जयपुर	67.92	17.	जयपुर	67.92
13.	कबीरधाम	60.85	18.	कबीरधाम	60.85
14.	सरगुजा	50.01	19.	सरगुजा	50.01
			20.	सूरजपूर	60.95
			21.	बलरामपुर	57.98
15.	बस्तर	54.4	22.	बस्तर	53.15
			23.	कोण्डागांव	56.21
16.	नारायणपुर	48.62	24.	नारायणपुर	48.62
17.	दन्तेवाड़ा	42.12	25.	दन्तेवाड़ा	48.63
			26.	सुकमा	34.81
18.	बीजापुर	40.86	27.	बीजापुर	40.86
	कुल	**70.28**		**कुल**	**70.28**

उद्देश्य

1. छ.ग. में ि"ाक्षा के क्षेत्र में हो रहे आउटसोर्सिंग जैसे प्रयोग का विरोध करना।
2. क्षेत्रीय योग्यता को बढ़ावा देना।
3. छ.ग. के ि"ाक्षित मानव संसाधनों को आंकड़ों द्वारा प्रदर्ि"ात करना।

सरकार ने अपनी तरफ से ये अलग तरह की पहल की है। उनका कहना है कि बार–बार इन आदिवासी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले गये लेकिन इन क्षेत्रों में किसी ने रूचि नहीं दिखाई इसलिए छ.ग. सरकार शिक्षकों की व्यवस्था बाह्य एजेन्सियों के माध्यम से करने का प्रयास कर रही है। छ. ग. के सरकारी आकड़ों के अनुसार शिक्षकों के कुल 2,19,933 स्वीकृत पदों में से, 45232 राज्य में खाली पड़े है। यह पहल विषे"ा रूप से ग्रामीण और दूरदराज, के क्षेंत्रों से, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। यह नियुक्ति अस्थाई होगी उन्हे ''वैकल्पिक व्याख्याता के रूप में जाना जाएगा। इस बात का भरपूर विरोध विपक्ष एवं जनता ने किया है। और क्यों न करें? स्कूल के शिक्षकों की आउटसोर्सिंग से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर नकारात्मक असर पड़ेगा। बाह्य कंपनियों और एजेन्सियों के द्वारा बाहर से ऐसे शिक्षकों को लाना राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के साथ कुठराघात जैसा है।

उन शिक्षकों का चयन सीमित अवधि के लिए विकल्प है क्योकि बलरामपुर, बस्तर, बीजापुर, जशपुर, कांकेर, कोण्डागांव, कोरिया, नारायणपुर, सुकमा, सूरजपुर, और सरगुजा, जिलों में हाई एवं हायरसेकेण्डरी स्कूलों में गणित, भौतिकी, रासायन, जीवविज्ञान, अंग्रेजी और वाणिज्य विषय के लिए शिक्षकों की भारी कमी है। ऐसी व्यवस्था तब तक के लिए है जब तक जिला पंचायत अपने लिए उपयुक्त और इच्छुक, उम्मीदवार जो इन दूर–दराज क्षेत्रों में काम करन के लिए तैयार हो खोजने में सक्षम हो जाए।

ऐसी व्यवस्था के लिए एक प्रशंसनीय कथन कहा गया कि **''सरकार आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।''** पर क्या सरकार राज्य के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है? आउटसोर्सिंग का प्रमुख कारण यह है कि लगातार माध्यमिक, हाई और हायरसेकेण्डरी में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन शिक्षकों की अनुपलब्धता की समस्या बस्तर और सरगुजा डिवीजन क्षेत्रों में (जहा माओवादी बच्चों को लुभाने की कोशिश कर रहा है।) अधिक तीव्र है।

राज्य सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों के भवि"य कि सुरक्षा के लिए रायपुर में **''प्रयास''** विद्यालय संचालित है। जिसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 11वीं एवं 12वी में अध्ययनरत् छात्रों को विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जा रहा है। बस्तर एवं सरगुजा (अंबिकापुर) में भी ऐसे विद्यालय प्रारंभ किये जा रहे हैं जिससे अधिक से अधिक छात्र लाभान्वित हो।

शिक्षकों की समस्या के लिए दूरगामी सोच रख के प्रयास किये जाने चाहिए जिस तरह ''प्रयास'' विद्यालय स्थापित करके इन छात्रों को मदद मुहैया कराई गई है, ये छात्र उच्च शिक्षा से अच्छे रोजगार प्राप्त करके समाज गंगा में शामिल हो सकेंगे वैसे ही सरकार को बस्तर, सरगुजा, जयपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, इत्यादि दूरस्थ क्षेत्रों के मेधावी छात्रों का चयन करके उन्हें डी.एड. और बी.एड. भी करवाया जाना चाहिए। जिससे उन्हें उनके ही क्षेत्रों में शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया जा सके, और शिक्षकों की हो रही कमी की समस्या से निजात मिल सकेगा।

छ.ग. में मानव संसाधन का स्वरूप

यहां पर शिक्षा की दर 71.04% जो की भारत में 27वें स्थान पर है जो बहुत बुरा है।

अगर हम जनसंख्या की बात करें तो छ.ग. मानव संसाधन से भरा पड़ा है। केवल इस संसाधन को संवारने/सुधारने की जरूरत है।

छ.ग. में शिक्षा का स्वरूप

छ.ग. में शिक्षा की दर 71.04% है, जो कि भारत में 27वें स्थान पर है। यह बहुत पिछड़ा हुआ है, अगर हम रायपुरः अपनी तरफ का प्रयोग पहली बार एक में, छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में स्कूलों के लिए शिक्षण सेवाआ बाहर अनुबंध करने की योजना शुरू की है, इसे प्रभावी ढंग से आकर्षित करने और शिक्षका की पर्याप्त संख्या को बनाए रखने की जिम्मेदरी घर में प्रबंधन नहीं कर सकता कह रही है। अब निजी कंपनियों, फर्मो और एजेंसियों किराया और स्कूल के शिक्षकों को तैनात करेगा।

पहले से ही विभिन्न प्रस्तावों सरकार में गणित, भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी और वाणिज्य को पढाने के लिए शिक्षण सेवाओं की आउटसॉर्सिंग के लिए तकनीकी और वित्तीय बोली की मांग आमंत्रित किया जाता है। बलरामपुर, बस्तर, बीजापुर, जशपुर, कांकेर, कोन्डागांव, कोरिया, नारायणपुर, सुकमा, सूरजपुर और सरगुजा जिलों में हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों। निविदाएं तीन अक्टूबर को संबंधित जिलों म खोले जाएंगे। सफल बोलीदाताओं द्वारा प्रदान की षिक्षण स्टाफ ''वैकल्पिक लेक्चरर'' या हिंदी में अंपांसचपा अलींलंजं के रूप में जाना होगा, वे संबंधित एजेंसी के कर्मचारियों को हो जाएगा और कोई बिंदु पर वे सरकारी विभाग में रोजगार प्राप्त करने के लिए दावा करने की कोशिश करेंगे।

राज्य में पहले से ही दो लाख से अधिक की एक सेना राज्य में पहले से ही दो लाख से अधिक की एक सेना '' शिक्षा Kamris'', पंचायत निकायों द्वारा भर्ती की है और मानदेय आधार है, जो कई सेवाओं में नियमितीकरण की मांग मौकों पर हड़ताल पर चले गए था पर काम करते हैं और नियमित रूप से सरकारी कर्मचारियों के बराबर वेतनमान।

स्कूल शिक्षा मंत्री केदार कष्यप के अनुसार, जहां शिक्षकों की कमी नहीं है,'' उन्होने कहा। जावेद जाफरी 'इश्क हमेशा के लिए, हफिंगटन पोस्ट में रो एजेंट खेलने के लिए कोलम्बिया के द्वारा अनुशंसित हालांकि, विपक्षी आश्वस्त नहीं है। विधानसभा में विपक्ष के नेता टी एक सिंहदेव का कहना है कि स्कूल के शिक्षकों की आउटसोर्सिंग स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर नकारात्मक असर पडेगा। कंपनियों और एजेंसियों के बाहर से ऐसे शिक्षकों की बड़ी संख्या में लाना होगा, उन्होने कहा।

स्कूल शिक्षा विभाग के सूत्रों ने बताया कि इस आउटसोर्सिंग शिक्षकों तक समय का सीमित अवधि के लिए एक विकल्प है और अस्थायी उपाय नियमित प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती किया जा सकता है। चयनित बोली लगाने गणित, भैतिकी, रसायन, जीवविज्ञान, अंग्रेजी और वाणिज्य विषय के लिए आउटसोर्स शिक्षण सेवाएं प्रदान करने के लिए जब तक जिला पंचायतों के लिए अपने स्वयं पर उपयुक्त और इच्छुक उम्मीदवार जो विभिन्न दूरदराज के क्षेत्रों में काम करने के लिए तैयार कर रहे हैं खोजने के लिए सक्षम हो जाएगा।

आउटसोर्सिंग योजना का बचाव करते हुए उन्हान कहा कि छात्रों को माध्यमिक स्तर दाखिला लिया जा रहा है की संख्या हर साल बढ़ रही है, लेकिन शिक्षकों की अनुपलब्धता की समस्या बस्तर और सरगुजा डिवीजन क्षेत्रों में जहां माओवादियों ने बच्चों को लुभाने के लिए कोशिश कर रहा है में और अधिक तीव्र है और उनके गुना में युवा। '' किशोरावस्था बहुत ही संवेदनशील है, और बच्चों को स्कूलों में सार्थक और रचनात्मक गतिविधियों में लिप्त होने के लिए नहीं है, और उन्ह पढ़ाने के लिए विषय शिक्षकों के बिना प्रयोग में नहीं रहना है'', सूत्रों ने कहा।

प्रति ''शिक्षण सेवाओं की आउटसोर्सिंग'' पर एक 50 पृष्ठों के इस दस्तावेज के रूप म, सरकार जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र के लिए अंग्रेजी, वाणिज्य के लिए 185, विज्ञान के लिए 506,337 के लिए कुल 2,163 विकल्प व्याख्याताओं– 564 को नियुक्त करने की योजना बना रही है, और गणित और भौतिक विज्ञान कि साथ कि लिए 571 वि"ाय में चिंतित और बीएड में स्नाकोत्तर योग्यता के बाद।

गुंजाइश के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी और व्याख्याताओं का संबंध कर्तव्य की उपेक्षा की स्थिति में दंड को आकर्"ात करेगा।

सार्वभौम का तात्पर्य उस स्थान तथा वहां के समस्त लोगों से है,जिनका उपयोग शोधकार्य के लिए किया जा सकता है।

निष्कर्ष

आदिवासी बहुल बस्तर और सरगुजा संभाग के स्कूलों में शिक्षकों की आउटसोर्सिग को लेकर कांग्रेस पर पलटवार, शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने दावा किया कि विपक्ष आदिवासी बच्चों और राज्य के भवि"य के साथ खेल रहा था। राज्य सरकार ने इतना है कि वे इंजीनियरिंग और चिकित्सा क्षेत्र में अपने कैरियर बना सकता है। विज्ञान विषयों में आदिवासी बहुल बस्तर और सरगुजा संभाग के 12 जिलों के बच्चों को शिक्षा देना चाहता है। सरकार बच्चों खाली नहीं छोड़ सकते है, और यह एक अस्थायी व्यवस्था है। शिक्षकों के रिक्त पदों छ.ग. व्यवासायिक परिक्षामंडल के माध्यम से भरा जाता है। तो सरकार को अपने निर्णय को वापस लेने जाएगा, डॉ. रमन सिंह ने स्पष्ट किया है, जबकि पत्रकारिता के कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय और मास कम्युनिकेशन, रायपुर में पत्रकारों के एक समूह से बात कर। विपक्ष आदिवासी बच्चों के हित में शिक्षकों की आउटसोर्सिंग के मुद्दे को छोड़ देना चाहिए, उन्हाने कहा। सरकार आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस निर्णय से दोनों आदिवासी बहुल संभाग के स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने में मदद मिलेगी, मुख्यमंत्री जोड़ा। यह पता चला है कि राज्यसरकार ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से आदिवासी बहुल सरगुजा और बस्तर संभाग के स्कूलों में रिक्त पदों को भरने का फैसला किया। उच्च विद्यालयों के साथ ही दोनों डिविजनों उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान, अंग्रेजी और वाणिज्य जैसे विषयों के लिए शिक्षकों के लिए कई पद खाली है। इन रिक्त पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जा रहा है। यहा अलग से, डाक्टरों और आदिवासी बहुल बस्तर और सरगुजा संभाग में नर्सो के रिक्त पदों को भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जा रहा है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. मानव संसाधन वीकिपीडिया
2. उच्च शिक्षा के सशक्तिकरण में मानव संसाधन प्रबंध की भूमिका (छ.ग. के विशेष संदर्भ में) शोधग्रंथ
3. हितवाद न्यूज पेपर मई 19
4. टाईम्स न्यूज नेटवर्क सितंबर 18
5. मुस्कान सामान्य अध्ययन
6. सरकारी आंकड़े